



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 पौष 1931 (श0)  
(सं0 पटना 35) पटना, सोमवार, 11 जनवरी 2010

---

सं0 3/एम-45/2008—170

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

6 जनवरी 2010

विषय:—सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संस्थित कार्यवाही का कुप्रभाव के संबंध में।

सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि किसी सरकारी सेवक की सेवा-निवृत्ति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित रहने या आपराधिक कार्यवाही संस्थित रहने की स्थिति में सेवाकाल की देय प्रोन्नतियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं।

चूंकि सेवाकाल के आरोपों के कारण ही किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित या आपराधिक कार्यवाही संस्थित होती है, अतः जिस प्रकार सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही/संस्थित आपराधिक कार्यवाही के कारण विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष संकल्प सं0 7457, दिनांक 11 सितम्बर 2002 के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है उसी प्रकार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संचालित या सम्पूरित विभागीय कार्यवाही या संस्थित आपराधिक कार्यवाही के कारण भी विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने का आधार होता है।

अतः राज्य सरकार ने संकल्प सं0 7457, दिनांक 11 सितम्बर 2002 के क्रम में, यह निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा-निवृत्ति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है या सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही सेवा-निवृत्ति के उपरान्त

पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कार्यवाही में सम्पत्तिवर्तित की जाती है अथवा कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है तो ऐसे सेवा-निवृत्त सरकारी सेवकों के सेवाकाल की देय प्रोन्नतियों के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया भविष्य में आयोजित की जानेवाली सभी विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा तब तक अपनाई जाती रहेगी जब तक कि संबंधित सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अजय कुमार चौधरी,  
सरकार के उप-सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 35-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>